

LOK SABHA DEBATES

1

LOK SABHA

Wednesday, November 26, 1980/
Agrahayana 5, 1902 (Saka)

*The Lok Sabha met at Eleven of
the Clock.*

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Special Peace Force to Control Communal Riots

+

*122. SHRI LAKSHMAN
MALLICK:

SHRI K. MALLANNA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a special peace force to control communal riots and disturbances; and

(b) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA):

(a) and (b). The Government of India have recently decided to increase the strength of Central Reserve Police Force for providing relief and training to the other battalions of the Force and for assistance to States. Three of the battalions to be raised will be specially trained and equipped to tackle situations arising out of communal and caste conflicts. These battalions would be raised on the same basis as other C.R.P. battalions. However, it would be ensured that minorities, Scheduled Castes and

2

Scheduled Tribes are adequately represented in these battalions. These battalions would be fully mobile so as to reach the troubled spots within the shortest possible time. They would be trained in fire fighting techniques, giving medical relief, making feeding arrangements for victims wherever necessary, carry out small repairs to structures damaged in violence etc. so that they can render relief in a comprehensive way wherever they are deployed.

SHRI LAKSHMAN MALLICK: I would like to know whether these battalions would be posted in different parts of the country? If so, the names of the places where they are likely to be posted. Secondly, what would be the estimated additional expenditure to be incurred on the maintenance of these new battalions?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: It is very difficult to say now where it will be deployed. Wherever it is necessary and when the State demands we will deploy them. So far as the expenditure is concerned it will be Rs. 519.21 lakhs non-recurring and Rs. 304.62 lakhs recurring.

SHRI LAKSHMAN MALLICK: Will the hon'ble Minister call the Chief Ministers and I.Gs of police to find out as to how to deal with the communal problems of the country?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, this exercise has been done, because, Chief Ministers, Governors, and even the I.Gs. of Police and Home Secretaries were called and this was discussed at various times.

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri K. Mallanna—Not here. Mr. Niren Ghosh.

SHRI NIREN GHOSH: Sir, may I know from the hon. Minister whether it is a fact that in Moradabad, the P.A.C. itself (which is full of Hindu chauvinism) unleashed these riots and indulged in attacks of those Mussalmans who had assembled there at their Idgah? Sir, what is the real guarantee that if you create yet another force it will act impartially, because in our country there has been so much of militant chauvinism that almost all these elements are practically intractable. From our own experience we have found that the Eastern Frontier Rifles composed of the Gurkha battalions could behave impartially and riots were contained on that score. That is why I ask, what is the guarantee? What effective steps are you going to take to see that these Forces act impartially in those riots? We have seen that generally the police and the Administration do not act impartially and they instigate the riots and the flame of communal disturbances there.

MR. DEPUTY SPEAKER: What is your question?

AN. HON. MEMBER: Question is understood.

SHRI NIREN GHOSH: Question has been put.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, there is nothing new in creating these forces. It is simply an addition to the C.R.P. The Government decided to add three more battalions. Therefore this recruitment is made. We thought that there should be some training which should be given to them, so that in times of emergency, or in times of riot etc., they can be utilised.

Therefore, training is being given initially to these three battalions. Then, later on, this training will be imparted to the other battalions also.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Order please. Now, Shri Shivkumar Singh Thakur.

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि ये जो सी० आर० पी० में स्पेशल बटालियंस तैयार करने की कोशिश की जा रही है क्या ये जिला मुख्यालय में रहेंगी या उन क्षेत्रों में रहेंगी जहाँ पर कि साम्प्रदायिक तनाव होते हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जब सामने से आनरेबल मेम्बर ने पूछा था तभी मैंने कहा था कि ये स्पेशल बटालियंस नहीं हैं। दिस इज ए पार्ट ऑफ अयर रिक्रूटमेंट लेकिन इनको ट्रेनिंग ऐसी देनी है कि कभी न कभी जब ऐसी इवेंचुएलिटी अग्राइव हो तो ये मूव कर सकें। जहाँ तक इनको रखने का ताल्लुक है, ये दिल्ली में रहेंगी।

Immediately it can be air-lifted and it can reach the place where it is required to go. At the same time, Sir, I wish to clarify one thing. The hon. Member made some charge against the Police in Uttar Pradesh. It is not desirable to make such charges here in this House because Police is not involved in any violence.

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Chitta Basu—He is not here. Shri Parulekar.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Mr. Deputy Speaker, Sir, through you, I would like to ask..

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Everybody will get a chance.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Through you, I would like to know from the hon. Minister of State for Home Affairs: There are three parts of my question. Part (a) of my

question is this: Do the Government really feel that merely by increasing the strength of the C.R.P. and by giving representation to the minorities, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, communal riot can be averted? Is there no other method to control communal riots rather than to use force? That is Part A of the question. Now, part B is this: What exactly do you mean by minorities? May I know whether the word 'minorities' is to be construed *vis-a-vis* the State? For example, in the State of Jammu and Kashmir, the Hindus are in a minority. Therefore, what exactly do you mean by the word 'minorities'? This is part (b) of my question. Part (c) of my question is this: Do the Government feel that preventive steps should be taken to avoid the riots? If so, what steps are proposed to be taken by the Government to increase their strength?

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) डिप्टी स्पीकर सर, यह कहना कि सी० आर० पी० की संख्या बढ़ाने से दंगे खत्म हो जाएंगे यह तो मैं नहीं कहता, लेकिन इस बात के लिए, जहां भी जरूरत पड़े वहाँ सेंट्रल रिजर्व फोर्स स्टेट्स को सप्लाइ कर सकें, इतनी संख्या हमको चाहिए इसलिए 8 बटालियन बढ़ाने का हमने फैसला किया है।

जहां तक सेंट्रल स्पेशल पीस कीपिंग फोर्स का सवाल है वह भी इसका एक हिस्सा है और इसका क्लेरिफिकेशन भी हमने कर दिया था, कुछ क्रिटिसिज्म आया था कि हमें भरोसा नहीं रहा या माईनारिटी का भरोसा नहीं रहा, किसी स्टेट का या किसी फोर्स का, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हमें सब पर भरोसा है और सारी फोर्स ठीक तरह से काम कर रही है। कहीं वीकर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन कम है, वहाँ नहीं है। यह भी है कि हर फोर्स में हर इदारे में बुरा आदमी भी हो सकता है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सजा दें और इसके लिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं।

उनका दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार ताकत के बल पर इन बातों को रोक सकती है, यह बात गलत है। यह सच है कि जो क्रिमिनल नेचर के या जाति संबंधी दंगे फसाद हैं वे ताकत के बल से नहीं रोक सकते। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने यह भी तय किया है कि हमारे जो पीस कीपिंग और पीस लविंग लोग हैं उनका कोआपरेशन लिया जाए। इस संबंध में हमने अन्य पार्टियों से भी अपील की। आपको याद होगा कि इस महीने में हमारी दिवाली आई, दशहरा आया, मुहर्रम आई, बकरीद आई, इन दिनों में हमने सब प्रांतों को यह निदेश किया कि वे मलीवरेशन कमेटियां, मुस्तकिल कौमों की बनाई जाएं मुस्तकिल लोगों को तमाम संप्रदाय के लोगो को इन कमेटियों में रखा जाए। इसका बड़ा अच्छा असर हुआ, लोग शामिल हुए और अवाम ने गवर्नमेंट का साथ दिया। अगर ग्रमनपरस्त लोग जो अमन रखना चाहते हैं, वे हमारा साथ न देते तो हम इन दंगों को रोक नहीं सकते थे। इन दंगों के पीछे बहुत बड़ी स्क्रीम थी, हिन्दुस्तान को बरबाद करने की, तबाह करने की। ये मिसक्रिएंट एलीमेंट्स जो हिन्दुस्तान के हितों को ठीक नहीं समझते जो खुदगर्जी पर चलते हैं, ऐसे एलीमेंट्स का मुकाबला करने के लिए लोगों ने हमारा साथ दिया।

एक माननीय सदस्य : इनको आप पकड़ते क्यों नहीं ?

श्री जैल सिंह : हमने पकड़े हैं, लेकिन साथ साथ हम अवाम के कोआपरेशन से, प्यार से, परसुएशनरो, निगोसिएशन से तमाम काम करते हैं और अवाम को अदब के साथ अपने साथ लेते हैं।

तीसरी बात उन्होंने कही कि अल्प-संख्यकों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया था, अब नुमाइंदगी देंगे। यह बात नहीं है ?

हम ने समझा कि कहीं कहीं अल्पसंख्यकों और वीकर सेक्शंस के लोगों की प्राप्ति नुमाइंदगी नहीं है वहां पर मिले, बल्कि हम चाहते हैं कि उनको उनके हिस्से से ज्यादा तरजीह दी जाये ताकि उनको सेटिस-फाईड किया जा सके ।

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. M. C. Daga.... (Interruptions) Those who have raised their hands will get a chance.

(Interruptions)

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब वे सच्चे हैं उनका जवाब देना रह गया था । आपने अल्पसंख्यकों के बारे में पूछा था । जे एण्ड के में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं और पंजाब में अल्पसंख्यक सिक्ख नहीं हैं और उसी तरह से नागालैण्ड या अन्य प्रांतों में जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक वहीं हों जो तमाम हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यक हैं मगर यह एक नेशन है और स्टेट को बाद में कंसीडर किया जाता है । तमाम नेशन को सामने रखकर देखा जाता है और विचार किया जाता है कि अक्लियतें कौन हैं, भाषा के हिसाब से या किसी और तरीके से, जो भी अक्लियतें हैं, उनका ख्याल रखना सरकार अपना परम धर्म समझती है ।

श्री मूल चन्दा डगा : शान्ति बल की बात आपने कही है । मैं समझता हूँ कि गोली से शरीर को दबाया जा सकता है मन को जीता नहीं जा सकता । शान्ति बल क्या सी० आर०पी० पर और खर्च करके बनाया जाएगा ? उनको बना देने से ही क्या आप समझते हैं कि प्रिवेंटिव मैशर्ज पूरे हो गए है ? प्रिवेंटिव मैशर्ज के लिए आप क्या यहीं जरूरी समझते है कि पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया जाए और उसी से ये दंगे हक जायेंगे ? मैं समझता हूँ कि शान्ति बल ऐसे लोगों का होना चाहिये

जो यह मानते हों कि मन पर लोगों के प्रभाव डाला जाए । क्या आप इससे सन्मत हैं ?

श्री जैल सिंह : मैं समझता था कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है । मैं फिर क्लीयर करना चाहता हूँ । शान्ति बल को बढ़ाने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जोर से ताकत से सब काम किया जाए उसका मतलब यह है कि तुरन्त कार्रवाई की जाए । जहां फोर्स की जरूरत हो वहां वह फोर्स पहुंच जाए । यह जो स्पेशल पीस मैकिंग एक विंग बनाया है उसकी वजह यह है कि वह मेडीकल एड दे सके, फायर फाइटिंग का काम भी कर सके या कोई और सहायता देनी हो तो वह भी दे सके उसको स्पेशल ट्रेनिंग हम देंगे ताकि वह इन कामों को कर सके । लेकिन हमारा विश्वास है कि मन को जीते बगैर, लोगों में आपस में प्यार और मुहब्बत पैदा करने वाली ताकतों को बढ़ाए, बगैर शान्ति नहीं हो सकती है ।

श्री ज. एम. बनातवाला : हकूमत की तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और उस पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए । लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस ने इन मुकामात पर दरिदगी का मुजाहिरा किया है और पुलिस एट्रिसिटीज की शिकायतें हम ने होम मिनिस्टर के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने भी रखी हैं । क्या हकूमत यह बताएगी कि इस किस्म के रिप्रेजेंटेशन पुलिस के खिलाफ उनकी बरबोरियत के खिलाफ उनकी दरिदगी के खिलाफ जो आज भी जारी है, उनको मिले हैं और अगर मिले हैं तो उनके ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की है मैं जानना चाहता हूँ कि किस बिना पर आज हकूमत में यह जरूरत पैदा होती है कि

वह इस एवान के सामने यह गलत बात कहे और पुलिस को सर्टिफिकेट दे ?

अभी कहा गया कि पीस फोर्स बनाई जा रही है और अगर स्टेट्स मांगेंगी तो इस फोर्स को उन को दिया जाएगा । बात यह है कि सारी शिकायतें ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हैं । यह पीस फोर्स फिर वहां जा कर उन्हीं पुलिस सुपरिटेण्डेंट्स और उन्हीं लोगों के अंडर काम करेगी और तब क्या उस की कारकर्मगी वैसी ही नहीं रहेगी ?

यह कहा गया है कि माइनोरिटीज को एडीक्वेट रिप्रिजेंटेशन दिया जायेगा । मैं जानना चाहता हू कि एडीक्वेट से आपका क्या मतलब है ? मुसलमानों को इसके अन्दर कितने परसेंट तनासुब दिया जाएगा ? इस बात की भी वजाहत की जाए ।

[श्री जी - ایم بلات والا :

حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پولیس نے بہت اچھا کا. کہا ہے - اور اس پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا چاہئے - لیکن حقیقت یہ ہے کہ پولیس نے ان مقامات پر درندگی کا مظاہرہ کیا ہے اور پولیس ایٹو اسٹیٹ کی شکایتیں ہم نے ہم ماسٹر کے سامنے درائم ماسٹرو کے سامنے بھی رکھی ہے - کہا حکومت یہ بنائے گی کہ اس قسم کے ریپریزیٹیشن کے خلاف ان کی ہر ہریت کے خلاف ان کی درندگی کے خلاف جو آج بھی جاری ہے ان کو ملے ہوں اور اگر ملے ہوں تو ان کے اوپر انہوں نے کیا کارروائی کی ہے - میں جاننا

چاہتا ہوں کہ کس بلٹا پر آج حکومت میں یہ جرت پیدا ہوئی ہے کہ وہ اس ایوان کے سامنے یہ غلط بات کہیں اور پولیس کو سرٹیفیکٹ دیں -

ابھی کہا گیا کہ پوس فورس بدلی جا رہی ہے - اور اگر اسٹیٹس مانگہں گی تو اس فورس کو ان کو دیا جائے گا - بات یہ ہے کہ ساری شکایتیں ہی لوکل ایڈ مینسٹریشن سے ہے - یہ پوس فورس پھر وہاں جا کر انہوں پولیس سوپرینٹنڈنٹس اور انہوں لوگوں کے اندر کام کریگی اور تب کیا اسکی کارکردگی ویسی ہی نہیں رہے گی - یہ کہا گیا ہے - مائلوریٹیج کو ایڈیکویٹ ریپریزیٹیشن دیا جائے گا - میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایڈیکویٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے - مسلمانوں کو اس کے اندر کتنے پرسیسٹنس مناسب دیا جائے گا - اس بات کی بھی وضاحت کی جائے [

श्री जैल सिंह : पुलिस फोर्स के खिलाफ एक सेक्शन पुलिस का जो था उस के खिलाफ, शिकायतें सरकार को दी गई हैं, यह सही बात है उन पर हम जानकारी कर रहे हैं । लेकिन जब मैंने कहा था कि पुलिस की तमाम फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया था तो उसका मतलब यह हांगज नहीं कि मैं कहता हू कि किसी फोर्स पर समुचे तौर पर बेएतबारी की जाए और ऐसा करना दुइस्त बात नहीं है । किसी फोर्स में कुछ आमदी ज्यादा गड़बड़ करे वाले भी हो सकते हैं, मुस्त भी हो सकते हैं, नाअहल भी हो सकते हैं, कोई शरारत जानबूझ कर करने वाले

भी हो सकते हैं, यह तो हम मानते हैं, लेकिन तमाम फोर्स को कहा जाए कि बही जिम्मेदार हैं, यह उचित नहीं है। मानदोय सदस्य ने कहा है कि स्टेट्स के मांगने पर ही हम उन्हें पुलिस फोर्स देंगे यह कायदे की बात है, स्टेट और सेंटर के रिलेशनस की बात है। यही अभी तक चला आ रहा है कि जब स्टेट मांगती है, तभी हम उसको फोर्स देते हैं। मैं विश्वास रखना हूँ कि हिन्दुस्तान की स्टेट सरकारें खाह वे किसी भी पार्टी की हों, यह नहीं चाहती कि दंगा फसाद हो और किसी वीकर सेक्शन, हरिजनों या माइनारिटी के लोगों को दबाया जाये। मैं यह भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात हो कि स्टेट गवर्नमेंट अकलियतों को प्रोटेक्शन नहीं देती है, हरिजनों और वीकर सेक्शन को प्रोटेक्शन नहीं देती है, तो हम इस बात का इन्तजार नहीं करेंगे कि वह स्टेट हमसे मदद मांगती है या नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ख्याल रखेगी और उन लोगों को प्रोटेक्शन दिया जायेगा।

SHRI NIREN GHOSH: How can it be?.... (Interruptions).

SHRI ZAIL SINGH: I can explain to you that.

माननीय सदस्य ने पूछा है कि माइनारिटीज को एडीक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने का क्या मतलब है। मतलब यह है कि बाज दफा रेक्यूटिंग एजेन्सियां माइनारिटी के लोगों को इग्नोर कर देती है, वह हम नहीं करने देंगे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कितने परसेंट लोग रखे जायेंगे, यह परसेंटेज की बात नहीं है। सविसेज में मैजारिटी या माइनारिटी के रिलिजन पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन है, तो सिर्फ इकानिमिक वेसिस पर, शिड्यूलड कास्टस और शिड्यूलड ट्राइब्ज

के लिए, या कुछ सविसेज में एक्स सविसेज में के लिए रिलिजस बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं है लेकिन हमने हिदायतें दे रखी है कि इस बात का ख्याल रखा जाये कि माइनारिटी के लोगों को उनकी आबादी के तनासुब से ज्यादा नुमायंदगी दी जाये, ताकि उनको कोई शिकयत न रहे।

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sontosh Mohan Dev.... (Interruptions).

AN HON. MEMBER: Why that side alone?.... (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down...How have you come to the conclusion that I will not call you. I will call you; you will have to wait..... (Interruptions).

SHRI JYOTIRMOY BOSU: **

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are not concerned with anything. Do not bring extraneous things here. Everyone who has given his name will be given a chance.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Under what rule have you accepted the names?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have noted down the names of the Members who raised their hands. I am calling them one by one. Shall I read out the names?....Those who have caught my eye, I have noted their names. They shall be called one by one.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On a point of order....(Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: No point of order in question hour.... Everybody shall get a chance. You have to wait and see.

SHRI NIREN GHOSH: The Minister has to explain something which he

has not explained. How can the Centre send the forces without being asked by the State? (Interruptions).

SHRI JANARDHANA POOJARY: **
(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will go through the proceedings. (Interruptions) I will go through it.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to know whether it is a fact that during the last two-and-a-half years of previous Janata rule there were infiltration in Services of RSS people in the police force as a result of which there is disruption and disorder in the police force. While recruitment is being done in the proposed police force, the Government should take care only of those people who are not committed to communal organisations like the RSS. They must not be recruited in this way. Is it the first time in the world that a Government is trying to form a secular police force to protect the interests of the minorities? I would like to know this from the hon. Minister.

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर का जो सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा लेकिन दूसरी तरफ जो सवाल के बगैर बोलते रहे हैं, वे जब सवाल करेंगे तब उनका जवाब दूंगा ।

आपका सवाल था कि क्या जनता राज में, आर एस एस जैसी जो ताकतें थीं, उनको सर्विसेज में तरजीह दी गई जिसकी वजह से कम्युनल लोग उसमें घुस गए और उसका असर सर्विसेज में आगे जाकर पड़ा—यह बात यहां तक सही है कि पिछले वक्त में जनता राज में फिरकेवाराना और कास्टीयन पर विश्वास रखने वाली ताकतों की हीसला अफजाई हुई, उनके रस्पेक्टेबिलिटी मिली और साथ साथ सर्विसेज में जब

भर्ती की जाती रही तो उनको तरजीह मिलती रही । मैं इस बात को इस तरह से नहीं कहता कि उन्होंने यह कहकर भर्ती की कि यह आर एस एस का है इसलिए इसको ले लिया जाए लेकिन बहुत होशियारी से ऐसे लोगों की भर्ती जरूर की गई । यही वजह थी कि आनरेबल मेम्बर ने कहा कि हमने शिकायतें दी थीं तो शिकायतें मिली हैं और हमने कुछ ऐक्शन भी लिया है, आगे भी कुछ ऐक्शन लेंगे । लेकिन हम इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि सर्विसेज में आने वाला किसी भी पार्टी के नेता का बेटा हो तो उस पर रुकावट डाली जाए पर इस बात का ध्यान रखना निहायत जरूरी है कि कास्टीयन का जो प्रिम्बल है कि हम सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और डिमोक्रेसी पर विश्वास रखेंगे ऐसे लोगों की भर्ती के लिए आइन्दा प्रबन्ध किया जाए ।

SHRI P. J. KURIEN: Sir, I want to know only one point from the Minister. Deputy Speaker, Sir, you have stated that additional posts are being created for dealing with communal violence and adequate representation will be given to minorities and scheduled castes. But recently in some of the newspapers, there appeared a news item that oral instructions have been given that candidates from a particular State,

AN HON. MEMBER: Which State?

SHRI P. J. KURIEN: It is Kerala State. I am only saying what I read in two or three Malayalam dailies. It appeared in some of the newspapers. I am only saying what I read in the press. I read that there are oral instructions that candidates from a particular State should be avoided. I want to know from the Minister whether any such instructions have

been given to the recruiting officers that candidates from that State should be avoided. If so, what is the reason behind it?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: No such instructions have been given. No such instructions have been issued to any officer for not recruiting. *(Interruptions)*

PROF. P. J. KURIEN: I read it in the paper. That is what I am saying. *(Interruptions)* My question which has been asked is bonafide. *(Interruptions)*. It is ridiculous; it is unparliamentary. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY SPEAKER: I will go through the proceedings. *(Interruptions)*

PROF. P. J. KURIEN: I read it in the paper. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY SPEAKER: Please sit down.

PROF. P. J. KURIEN: It is ridiculous; it is unparliamentary. You please ask him to withdraw it.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : No such instruction is given to any officer not to recruit from any particular State. So far as Kerala is concerned, when I visited there I made amply clear that we were going to recruit from Kerala also. *(Interruptions)*.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will call you. Every one of you shall be called. I give you this assurance. Whoever catches my eyes shall be called. You please give me some time. Shri Rajesh Pilot.

SHRI RAJESH PILOT: Any amount of peace force or any amount of very exciting speech by the hon. Home Minister will not ease the communal riots and the disturbances in this country. May I know from the Home

Minister through you what positive steps the government is planning to take to check the activities of political parties who are involved directly or indirectly in communal riots for their political gains?

(Interruptions)

SHRI YOGENDRA MAKWANA : The hon. Home Minister has very clearly stated in reply to the question of the previous member that the force cannot control these riots. It is ultimately the society which has to keep in mind that communal harmony is to be maintained. So far as political parties are concerned, when such instances are brought to the notice of the government and when direct interest is taken by any political party, necessary action will be taken against it.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Communal riots cannot take place without money supply and passive or active or both support from the local administration, police and the local ruling party. In Moradabada case, the riots took place because of the tirade of the communal people who wanted to discredit the present Chief Minister, MR. V. P. Singh. That is the root cause of the Moradabad riots. There is not doubt that.**

**

(Interruptions)

THE PRIME MINISTER (SHRI-MATI INDIRA GANDHI): I resent these allegations against my party.

(Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BOSU:**

(Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You have seen the photographs. *(Interruptions)*

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND ELECTRONICS (SHRI C. P. N. SINGH): Is he asking a question? He is making

an allegation. (*Interruptions*) He may ask a question. Why is he making an allegation?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Whatever anybody says shall not go on record including Mr. Jyotirmoy Bosu.

(*Interruptions*)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Rule 353. Mr. Jyotirmoy Bosu, you are a very senior leader and a learned and knowledgeable person. No allegation please. Rule 353 says as follows:

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter...."

No allegation. You put a question and get information.

(*Interruptions*)

Please put the question. No allegations. Whatever you have stated with regard to any political party or any other Member of this House—I shall see the proceedings, I shall see if there are any allegations and if I find anything wrong, I will expunge it... (*Interruptions*). It will not be proper to charge the ruling party because in West Bengal his is the ruling party.... (*Interruptions*) In a friendly way

PROF. MADHU DANDAVATE: I want a clarification about your ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I read out the rule; I will abide by the rules.

PROF. MADHU DANDAVATE: I agree with you that according to the rule no allegation can be made against individuals but against the government, against party, I think every opposition Member has a right to make allegations and make charges.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If it is defamatory? That right I have got. You may read the proviso also.

It says:

"Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served; by making such allegation."

SHRI K. LAKKAPPA: I would like to make a submission. Thirty minutes have been taken for this question. How can you allow this? What about other questions?

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: I want to put a question.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have already allowed Mr. Banatwalla; one from each party. Shri Jyotirmoy Bosu.

(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Would you bring the House to order?

(*Interruptions*)

श्री रामस्वरूप राम : मेरा व्यवस्था का प्र.न है . . . (व्यवधान) . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will call every one of you. Please sit down.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: **

(*Interruptions*)

SHRI K. LAKKAPPA : He must abide by the rules.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: **

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is whether the government proposes to set up a special peace force to control communal riots and disturbances and if so the details in this regard. If you want any details

*Not recorded.

**Expunged as ordered by the Chair.

in that regard you can put that question. I will not allow any other thing.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: In the context of your observation....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only with regard to that subject-matter a question can be put.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have read out the question. Only supplementaries pertaining to that question will be allowed. I cannot allow any other extraneous things.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: If you will kindly bear with me, in half a minute I will ask my question. I do not believe that, by raising additional forces of a mercenary type it is going to help preventing riots in future. This is my own opinion; that is why I asked about involvement of political parties

My question (b) is, arising out of the reply, since the cat is out of the bag, will the Hon. Minister tell us whether, very recently, there had been a conference of CRP IGs, Director Generals and Directors in Delhi and if so, in that meeting whether a decision has been taken not to recruit any people from Kerala, West Bengal and Tripura for political reasons.

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर ने यह कहा है कि सी० आर० पी०, एस० पी० की मीटिंग बुलाकर उममें हमने यह हिायेते दी है कि कोच या कूड और एरिये के लोगों को उसमे भर्ती न किया जाए, यह वि सुल बेसबेस है. गलत है, बेबुनियाद है । (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing not pertaining to this question will go on recorded. (Interruptions).**

All these things will not go on record. (Interruptions).**

Dr. Subramaniam Swamy.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I would like to know....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Only pertaining to this question.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Yes, I will ask a question only pertaining to this. I am not Jyotirmoy Bosu!

Government must clarify, through their replies, in precise terms. Mr. Makwana has said that the force will be fully mobile: it means it will not be stationary. But the Home Minister says that the force will be mobile only when called for. That means, sometimes it will be mobile and sometimes not mobile. (Interruptions).

This is the problem with the Home Ministry. The two Ministers must work together but they seem to be working at odds with each other. (Interruptions). Therefore, I would like to know, when he uses a phrase that 'adequate representation would be given to minorities', whether the Government is going to honour the written agreement signed between Mrs. Indira Gandhi and Shahi Imam of Jama Masjid where she agreed in writing that if elected to power she will ensure that minorities will get a fixed representation and ratio in the Army, Air Force and Navy. Government should clarify whether they are going to live by their word or not.

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, यह मैं बड़े अदब से इस हाउस के सामने कहता हूं कि आनरेबल मेम्बर साहब ने जो मायने निकाले हैं वे बिल्कुल गलत निकाले हैं । हमारे मिनिस्टर और मिनिस्टर आफ स्टेट के विचारों में, ख्यालों में और स्टेटमेंट में कोई भी अन्तर नहीं है । एक ही तरह का हमने जवाब दिया है ।

दूसरी बात जो उन्होंने कही कि किसी के साथ कोई प्राइम मिनिस्टर का एग्जीमेंट हुआ, यह बात शाही इमाम के लिए कही, उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है ।

उनसे क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, यह मैं नहीं कह सकता और ना ही इस क्वेश्चन में यह बात है। मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम रिजर्वेशन के बेसिस पर कोई रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, न करना चाहते हैं और न करने का इरादा है। यहां सेक्युलर कांस्टीट्यूशन है, सेक्युलर स्टेट है। हमारा फर्ज सिर्फ इतना ही है कि उनको नैगलेक्ट न होने दे, कोई उनको दवा न सके, उनका जो हक बनना है वह उन को मिले।

Arrears of Provident Fund in Maharashtra

*123 SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of LABOUR be pleased to lay a statement showing:

(a) the total arrears in respect of provident fund contributions of the employers in Maharashtra State;

(b) the total arrears in respect of amounts deducted from employees but not deposited with the Provident Fund Commissioner by the said employers;

(c) whether Government are contemplating any additional/new provisions in the Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act to control and reduce this incidence of default; and

(d) if so, what are the proposed measures?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI MATI RAM DULARI SINHA): (a) to (d). A statement is laid on the table of the House.

Statement

The Employees' Provident Fund authorities have reported as under:--

(a) A sum of Rs. 627.37 lakhs (both employers' and employees'

share) was outstanding as on 30-6-1980 from unexempted establishments in Maharashtra State. Another sum of Rs. 38.24 lakhs was also outstanding from exempted establishments in Maharashtra.

(b) A sum of Rs. 202.07 lakhs was outstanding against employers, as employees' contributions, to be deposited with the Regional Provident Fund Commissioner as on 30-6-1980.

(c) and (d). In order to curb the mounting arrears of provident fund dues and to make the penal provisions more stringent, the following legislative proposals are under the consideration of the Government:

(i) Amendment of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 to make the offences under the Act as continuing ones so that they may not be barred by the period of limitation prescribed in Section 468 of the Criminal Procedure Code and the Courts may take cognizance of the prosecutions filed by the organisation against defaulting establishments without limit of time.

(ii) to provide for the provident fund arrears being recovered as 'Public Demand'.

(iii) to provide for the dues representing the contributions of the employers as well as the employees to the Employees' Provident Fund, Family Pension Fund and the Employees' Deposit-linked Insurance Fund being given first priority in the distribution of assets of the defaulting establishments going into liquidation or ordered to be wound up by a Court.

(iv) to amend section 8 of the Act so that the amount in default from exempted establishments may also be recovered as arrears of land revenue.

(v) to amend section 14B of the Act to bring within its scope the exempted establishments also so